

प्रेस विज्ञप्ति 3/11/2025

ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 से अधिक संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 30 संपत्तियां, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की 5 संपत्तियां, मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की 4 संपत्तियां, गमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विहान43 रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की 1-1 संपत्ति और कैंपियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की गई है।

परिसंपत्तियों में पाली हिल आवास तथा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी की संपत्तियां शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर 2025 को कुर्की आदेश जारी किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से संबंधित विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी ₹3,083 करोड़ से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए।

कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह रोड स्थित रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सिंहत) और पूर्वी गोदावरी में स्थित कई संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों में कार्यालय परिसर, आवासीय इकाइयाँ और भूखंड शामिल हैं। चारों आदेशों का कुल कुर्क मूल्य लगभग ₹3,084 करोड़ है।

अब तक, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल),रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), रिलायंस



इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) और रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) सिहत विभिन्न रिलायंस अनिल अंबानी समूह कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन के धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण (डायवर्जन) का पता लगाया है।

2010-12 के आसपास, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने भारतीय बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपये लिए, जिनमें से ₹19,694 करोड़ अभी भी बकाया हैं। ये संपत्तियाँ गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) में बदल गईं, परिणामतः पाँच बैंकों ने आरकॉम के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि एक संस्था द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋणों का उपयोग अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋणों के स्वीकृति पत्र के निबंधन और शतों का उल्लंघन था। विशेष रूप से, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने ₹13,600 करोड़ से अधिक का उपयोग ऋणों को नियमित बनाए रखने के लिए किया, ₹12,600 करोड़ से अधिक को संबंधित पक्षों को हस्तांतरित (डायवर्ट) किया गया और ₹1,800 करोड़ से अधिक का निवेश एफडी/एमएफ आदि में किया गया, जिसे समूह संस्थाओं में पुनर्निवेशित करने के लिए बड़े पैमाने पर नकदीकरण किया गया। ईडी ने संबंधित पक्षों को धन पहुंचाने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का भी पता लगाया है। कुछ ऋणों को विदेशी बाह्य प्रेषणों (रेमिटेन्स) के माध्यम से भारत के बाहर भेजा गया था।

2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल की परियोजनाओं में ₹2,965 करोड़ और आरसीएफएल के योजनाओं में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया। दिसंबर 2019 तक, ये गैर-निष्पादित निवेश बन गए। आरएचएफएल के लिए बकाया राशि ₹1,353.50 करोड़ और आरसीएफएल के लिए ₹1,984 करोड़ हो गई।



आरएचएफएल और आरसीएफएल मामले में ईडी की जाँच से पता चलता है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल को ₹10,000 करोड़ से ज़्यादा की सार्वजनिक धनराशि प्राप्त हुई। इसमें से एक बड़ी राशि यस बैंक से आई थी। यस बैंक द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में यह धनराशि निवेश करने से पहले, यस बैंक को पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी धनराशि प्राप्त हुई थी। सेबी के नियमों के अनुसार, हितों के टकराव के नियमों के कारण, रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड, अनिल अंबानी समूह की वितीय कंपनियों में सीधे निवेश/धन का हस्तांतरण नहीं कर सकता था। इसलिए, म्यूचुअल फंड योजनाओं में जनता का धन अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा निवेशित किया गया। यह रास्ता यस बैंक के ऋणों के माध्यम से तय हुआ। सार्वजनिक धन अनिल अंबानी समूह की कंपनियों तक सर्किटनुमारास्ते से पहँचा।

आरएचएफएल और आरसीएफएल ने 35 से ज़्यादा बैंकों और वितीय संस्थानों से उधार लिया था। ऋणों का एक बड़ा हिस्सा चुकाया नहीं गया। इनमें से ज़्यादातर ऋणों को हस्तांतिरत (डायवर्ट) कर दिया गया। यह हस्तांतरण (डायवर्जन) समूह की कंपनियों को आगे ऋण देकर किया गया। यह रूटिंग कई शेल संस्थाओं के ज़िरए हुई, जिन पर रिलायंस अनिल अंबानी समूह का प्रभावी नियंत्रण था। सार्वजनिक धन को कॉर्पोरेट ऋणों और अंतर-कॉर्पोरेट जमाओं की आड़ में स्थानांतिरत किया गया। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा पहुँचाया गया।

बैंक स्टेटमेंट में धन शीघ्र हस्तांतरण दिखाई देता है। मिनटों में ही विभिन्न संस्थाओं के खातों के बीच बहुत बड़ी रकम के लेन-देन का पता चला। हालाँकि आरएचएफएल एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन इसके ऋण खाते कॉर्पोरेट ऋणों की ओर अधिकाधिक परिणत हुए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने नियामक उल्लंघनों के लिए आरएचएफएल पर जुर्माना लगाया। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट ऋणों की वसूली को लेकर अनिश्चितता की ओर इशारा किया। कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के तहत एक धोखाधड़ी रिपोर्ट भी दर्ज की गई। बाद में, राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने प्रमुख प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए



लेखा परीक्षक को दंडित किया। सेबी ने भी कंपनी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।

वास्तिवक व्यक्तियों/व्यवसायों के लिए, ऋण स्वीकृति से पहले समुचित सावधानी - आवेदन, सिबिल, केवाईसी, क्षेत्रीय जाँच, मूल्यांकन, कानूनी जाँच और प्रतिभूति निर्माण की आवश्यकता होती है। इस मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने इसके बजाय दुर्भावना का एक पैटर्न पकड़ा है, जिसमें पूर्व-निर्धारित लाभार्थी, मनगढ़ंत कागजी कार्रवाई, नियंत्रणों से छूट, और मंजूरीपूर्व ही धन का संवितरण, तदोपरांत संबंधित संस्थाओं को तुरंत धन हस्तांतरण देखा गया है। इस आचरण ने सार्वजनिक धन की हेराफेरी को संभव बनाया। आरएचएफएल और आरसीएफएल द्वारा दिए गए ऋणों से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण करते समय पाए गए कुछ ऐसे उल्लंघनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

मंजूरीपूर्व भुगतान: औपचारिक मंजूरी से पहले ही धनराशि जारी कर दी गई। कागजी कार्रवाई बाद में हुई। विवेकपूर्ण ऋण के अंतर्गत कालक्रम का निर्धारण असंभव है। यह पिछली तारीख और पूर्व-निर्धारित भुगतानों को दर्शाता है। उदाहरण:

- •.क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ₹7.00 करोड़ का संवितरण 20 अप्रैल 2018 को; मंजूरी और समझौता 26 अप्रैल 2018 को। छह दिन पहले।
- स्पीशीज कॉमर्स एंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ₹49.40 करोड़ संवितरित 21 अगस्त 2018; मंजूरी 22 अगस्त 2018।
- वर्ल्डकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड ₹49.40 करोड़ संवितरित 21 अगस्त 2018; मंजूरी 22 अगस्त 2018।.
- आरपीएल सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ₹49.40 करोड़ संवितरित 21 अगस्त 2018; मंजूरी 22 अगस्त 2018।
- आरपीएल स्टार पावर प्राइवेट लिमिटेड ₹49.40 करोड़ संवितरित 21 अगस्त 2018; मंजूरी 22 अगस्त 2018।
- आरपीएल सनलाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड ₹99.95 करोड़ संवितरित 27 मार्च 2018; मंजूरी 28 मार्च 2018।



एक ही दिन आवेदन-अनुमोदन-अनुबंध-संवितरण: बड़े कॉर्पोरेट ऋणों की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी कर दी गई। इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई में क्षेत्रीय जाँच, व्यक्तिगत चर्चा, कानूनी और तकनीकी जाँच, मूल्यांकन, एस्क्रो व्यवस्था या प्रतिभूति संबंधी दुरुस्ती के लिए समय ही नहीं बचा। उदाहरण:

- आरपीएल आदित्य पावर प्राइवेट लिमिटेड ₹139.50 करोड़। आवेदन, मंजूरी, समझौता और संवितरण सभी 24 अगस्त 2018।
- आरसीएफएल से कुंजबिहारी/विहान43 क्लस्टर कई फाइलें थोक संवितरण के साथ एक ही दिन के चक्र को दर्शाती हैं।

आवेदनपूर्व मंजूरी: मंजूरियाँ उधारकर्ता के दस्तावेज़ों से पहले की हैं। पहले हुए अवैध भुगतान को छुपाने के लिए कालक्रम में हेरफेर किया गया था। उदाहरण:

• कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बाद में विहान43 रियल्टी) - मंजूरी 27 दिसंबर 2018; उधारकर्ता बोर्ड संकल्प और ऋण आवेदन 31 दिसंबर 2018।

अदिनांकित मंजूरी: क्रेडिट मूल्यांकन ज्ञापनों पर प्रस्तावक, अनुशंसाकर्ता और अनुमोदनकर्ता अधिकारियों द्वारा बिना तिथि के हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑडिट ट्रेल को छिपाने के लिए तिथियों की चूक की गई है। इससे अवैध रूप से कार्योत्तर मंजूरी संभव हुई।

निर्धारित उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग नहीं किया जाना: मंजूरी पत्र ऋण को किसी विशिष्ट परियोजना (उदाहरण के लिए, पाली हिल) से जोड़ते हैं। निष्पादित अनुबंधों में "सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य" लिखा है। हस्ताक्षरित अनुबंध में प्रतिभूति अनुसूचियाँ रिक्त हैं। यह फाइल में अनुपालन का दावा करते हुए धनराशि के हस्तांतरण में सहयोग देता है। उदाहरण:

• कुंजबिहारी/विहान43 - मंजूरी पाली हिल को प्रतिभूति के रूप में उद्धृत करती है; समझौता सामान्य है; अनुसूचियाँ रिक्त..



प्रतिभूति संबंधी मिथ्यानिरूपण और असुरक्षित ऋण।

प्रतिभूति अनुसूचियाँ रिक्त हैं। कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्क पंजीकृत नहीं हैं। सीएएम में उच्च प्रतिभूति मूल्यों का दावा किए जाने के बावजूद मूल्यांकन पत्र मौजूद नहीं हैं। यह एक भ्रामक रणनीति है और वसूली को नुकसान पहुँचाती है। कई मामलों में, चालू परिसंपत्तियों पर केवल अवशिष्ट शुल्क ही लिया जाता है। उदाहरण::

• कुंजबिहारी/विहान 43 - कोई आरओसी शुल्क नहीं; कोई मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं; रिक्त अनुसूचियाँ.

ऋण मंजूरी के समय विभिन्न कंपनियों को दी गई व्यापक छूट: सामान्य प्रयोजन कॉपॉरेट ऋण (जीपीसीएल), ऋण उधार प्रक्रिया में व्यापक रूप से ऋण प्रस्ताव तैयार करना, कंपनी के निबंधन और शतों के अनुसार उधारकर्ता का संपूर्ण विश्लेषण करना, क्रेडिट मूल्यांकन ज्ञापन (सीएएम) तैयार करना आदि शामिल हैं। क्रेडिट मूल्यांकन ज्ञापन (सीएएम) एक मानक प्रारूप है जो ऋण प्रस्ताव के सभी विवरण जैसे प्रस्तावक का नाम, उधारकर्ता का नाम, उधारकर्ता के सभी वितीय विवरण, उधारकर्ता के प्रमोटरों/निदेशक का विवरण, ऋण राशि का विवरण, इसके सभी निबंधन और शर्तें, क्रेडिट मूल्यांकन टीम के निष्कर्ष, मानक ऋण शर्तों से स्वीकार किए जाने वाले प्रस्तावित किसी भी विचलन का विवरण आदि का दस्तावेजीकरण करता है। उक्त कार्य क्रेडिट मूल्यांकन टीम द्वारा किया गया और विश्लेषण को सीएएम में "क्रेडिट समिति" के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, कई संदिग्ध उधारकर्ताओं को कई अवैध और अनुचित छूट दी गई थी, जिससे अंततः ऋणों की हेराफेरी हुई। ऐसी कुछ छूटों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- > एफआई (फील्ड इन्वेस्टिगेशन) में छूट;
- पीडी (व्यक्तिगत चर्चा) में छूट।
- > मानदंडों के अनुसार पात्रता नहीं;
- > अधिकतम ऋण मानदंडों के अनुसार नहीं है।
- 🕨 बिना प्रतिभूति संवितरण किया गया।
- > मूलधन एकबारगी हों (मासिक परिशोधन नहीं)।
- 🕨 ब्याज दर/पीएफ/मोचननिषेध शुल्क मानदंडों के अनुसार नहीं.
- > ग्राहक रेटिंग नहीं की गई; बिल्डर/तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया।



- > कोई एस्क्रो नहीं; कोई मासिक बुकिंग एमआईएस नहीं;;
- 🕨 नकदी प्रवाह विवरण नहीं लिया जाना।

कमज़ोर, गैर-परिचालन और मुखौटा उधारकर्ता।

उधारकर्ताओं ने कोई कर्मचारी नहीं होना, कम इक्विटी, नगण्य संपत्ति या शून्य राजस्व दर्शाया है। उदाहरण के लिए, आरपीएल आदित्य पावर प्राइवेट लिमिटेड का राजस्व शून्य था, फिर भी उसे ₹139.50 करोड़ मंजूर किए गए।

संबंधित पार्टियों द्वारा स्तरीकरण और सर्किटनुमा प्रक्रिया।

उधारकर्ता अनिल अंबानी समूह की संस्थाओं के साथ पते, निदेशक और लेखा परीक्षक साझा करते हैं। पर्याप्त ऋण सीएलई प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरइन्फ्रा) को दिया गया। कम से कम 13 कर्जदारों ने सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आरइन्फ्रा को ₹1,460 करोड़ से अधिक की राशि भेजी।

इसके अलावा, विरष्ठ अधिकारियों ने ऋण प्रसंस्करण टीमों को उधारकर्ताओं के नाम सुझाए। फिर दस्तावेज तैयार किए गए। ईडी ने उधार लेने वाली संस्थाओं में जिटल शेयरधारिता का भी पता लगाया। अंतिम लाभकारी मालिक को छिपाने के लिए तानाबाना डिज़ाइन किया गया था। निदेशकों के रिलायंस समूह की कंपनियों के साथ पिछले या समानांतर संबंध थे। कुछ उधारकर्ताओं को समूह के संबंधित पक्षों के रूप में प्रकट किया गया था। मंजूरी से ठीक पहले, खुलासे बदल गए ताकि वे बंधित पक्षों के रूप में दिखाई न दें। कई उधारकर्ताओं को साझा परिसरों में पंजीकृत किया गया था। उनके पास साझा निदेशक और साझा लेखा परीक्षक थे। ईडी की तलाशी में इन पतों पर कोई व्यावसायिक परिचालन नहीं मिला। ये फंड ट्रेल पूर्व-निर्धारित अंतिम उपयोग की पुष्टि करता है। ऋण राशि मिनटों में एक खाते से दूसरे खाते में भेजी गई। इस पैटर्न में परतीकरण (लेयरिंग) और राउंड-ट्रिपिंग दिखता है। हालाँकि, इसका उद्देश्य सार्वजनिक धन की हेराफेरी थी।



रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में फेमा के तहत एक अलग तलाशी और ज़ब्ती में जयपुर-रींगस राजमार्ग परियोजना से ₹40 करोड़ की निकासी का खुलासा हुआ है। सूरत स्थित फर्जी कंपनियों के ज़रिए यह धन दुबई पहुँचाया गया। इस सुराग से ₹600 करोड़ से भी ज़्यादा के एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का पता चला है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपराध की आय का पता लगाने में लगा हुआ है। ईडी द्वारा की जा रही वसूली, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, ऋणदाताओं को हुए नुकसान की भरपाई करने और अंततः आम जनता को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से की जा रही है।

कुर्की का विवरण:

- पाली हिल, मुंबई (बांद्रा पश्चिम): सीटीएस संख्या सी/1316बी/1/1; प्लॉट 43, नरगिस दत्त रोड। अंबानी परिवार के पाली हिल स्थित आवास के रूप में प्रसिद्ध।
- नई दिल्ली: रिलायंस सेंटर, नई दिल्ली।
- रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड: मुंबई, पुणे, ठाणे, नोएडा, हैदराबाद, पूर्वी गोदावरी और गोवा में अवस्थित कई संपत्तियाँ; जिनमें नागिन महल कार्यालय (चर्चगेट, मुंबई), बीएचए मिलेनियम टॉवर, (नोएडा) के फ्लैट, कैमस कैप्री अपार्टमेंट्स (हैदराबाद), पूर्वी गोदावरी में भूखंड, और पुणे व ठाणे में परिसर शामिल हैं।
- संबद्ध संस्थाओं की संपत्तियाँ: गाजियाबाद/नोएडा में भूखंड और चेन्नई (अड्यार/ओएमआर-कोट्टिवाक्कम) में 29 फ्लैट, जिनका मूल्य ₹109.61 करोड़ (समतुल्य मूल्य) है।

तस्वीरें अगले पृष्ठ पर हैं



पाली हिल, मुंबई (बांद्रा पश्चिम): सीटीएस संख्या सी/1316बी/1/1; प्लॉट 43, नरगिस दत्त रोड। अंबानी परिवार के पाली हिल स्थित आवास के रूप में प्रसिद्ध।

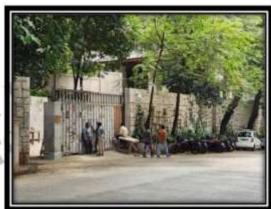














नई दिल्ली: रिलायंस सेंटर, नई दिल्ली।









रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड: मुंबई, पुणे, ठाणे, नोएडा, हैदराबाद, पूर्वी गोदावरी और गोवा में अवस्थित कई संपत्तियाँ; जिनमें नागिन महल कार्यालय (चर्चगेट, मुंबई), बीएचए मिलेनियम टॉवर (नोएडा) में फ्लैट, कैमस कैप्री अपार्टमेंट्स (हैदराबाद), पूर्वी गोदावरी में भूखंड गोदावरी, और पुणे और ठाणे में परिसर शामिल हैं।



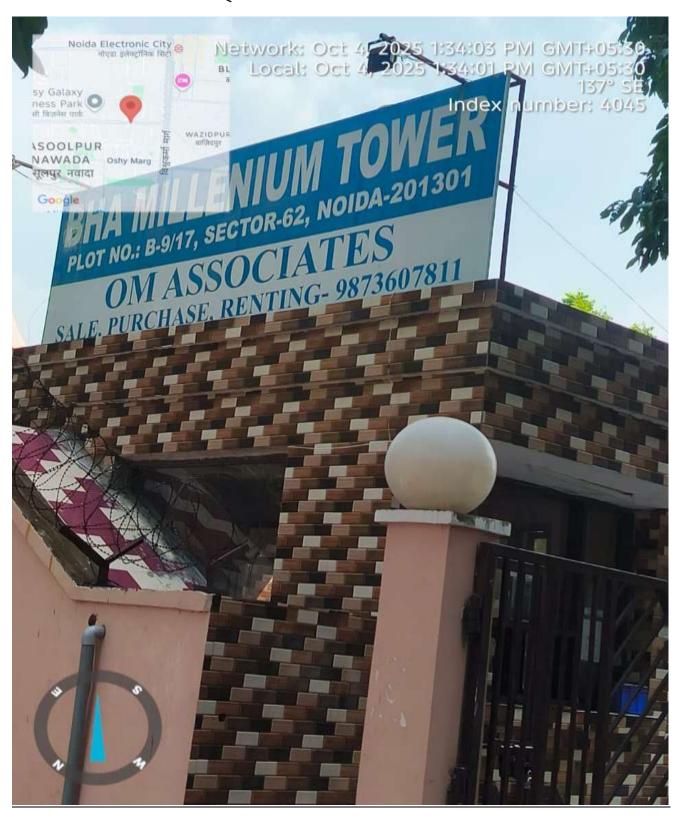
- 1. मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड (मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड का नाम बदलकर मेसर्स रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और आगे मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया) के नाम पर सात (7) अचल संपत्तियां:
- क) एक भूखंड संख्या ए-02, ब्लॉक ए, सेक्टर-24, इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।







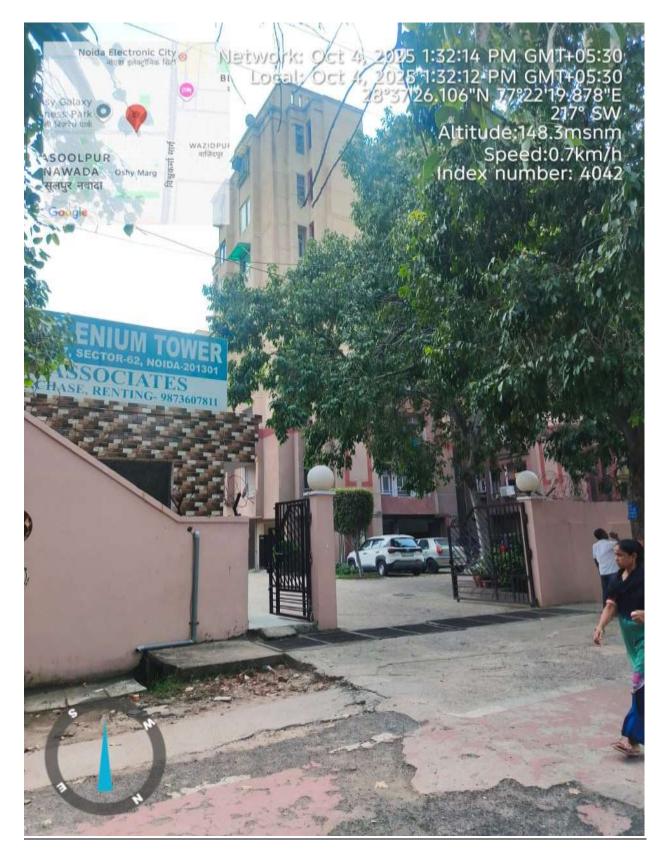
ख) छह फ्लैट यथा फ्लैट संख्या 114, 314, 402, 514, 712 और 714 बीएचए मिलेनियम टॉवर, बी-9/17, ब्लॉक बी, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201309।













1. मेसर्स बीएसईएस आंध्रा पावर लिमिटेड (मेसर्स बीएसईएस आंध्रा पावर लिमिटेड मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड में विलय हो गया। तत्पश्चात, मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड का नाम बदलकर मेसर्स रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और फिर मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया) के नाम पर पंद्रह अचल संपत्तियाँ:

क) दो फ्लैट यथा फ्लैट संख्या 201 और 202, द्वितीय तल, कैमस कैप्री अपार्टमेंट, सोमाजीगुडा, राजभवन रोड, हैदराबाद, तेलंगाना (नगरपालिका संख्या: 6-3-1090ए)।

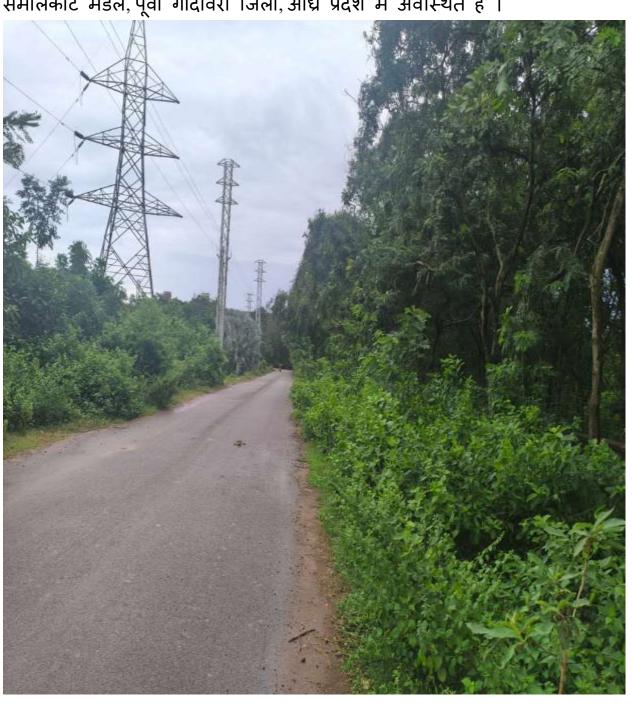








ख) छह अचल संपित्तयां यथा 2.87 एकड़ (सर्वेक्षण संख्या 932/1/बी), 2.67 एकड़ (सर्वेक्षण संख्या 932/1), 5.70 एकड़ (सर्वेक्षण संख्या 932/2 (भाग)), 6.90 एकड़ (सर्वेक्षण संख्या 932/1ए और 932/2पी), 1.56 एकड़ (सर्वेक्षण संख्या 931/1 (भाग) और 908/2 (भाग), 908/1ए और 909) भूखंड पेद्दापुरम गांव और नगरपालिका क्षेत्र, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में और सर्वेक्षण संख्या 35 भाग, 36 भाग, 37 भाग, 38 भाग, 39, 40, 41, 42 भाग, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 भाग, 71 भाग, 72, 73 भाग, 76 भाग, औद्योगिक विकास क्षेत्र, पेद्दापुरम, वेट्टापुरम गांव, समालकोट मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है ।























ग) सात अचल संपित्तयां सर्वे संख्या 268/1, 268/2, 268/3 और 268/6, सर्वे संख्या 293/10 भाग, भीमावरम गांव, और सर्वे संख्या 86/1, सर्वे संख्या 89/1 और 86/1, सर्वे संख्या 89/1, सर्वे संख्या 89/1ए और सर्वे संख्या 86/1 जग्गममुगारीपेट गांव, मंडल समालकोट, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

















3. <u>मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड (मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड का नाम बदलकर मेसर्स</u> रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और बाद में मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया) के नाम पर दो अचल संपत्तियाँ (एक फ्लैट और एक कार्यालय परिसर):

क) फ्लैट संख्या 5, द्वितीय तल, "नागिन महल", 82, प्लॉट संख्या 4, ब्लॉक संख्या 1, बैकबे रिक्लेमेशन एस्टेट, सरकार, बॉम्बे, वीर नरीमन रोड, चर्चगेट, म्ंबई।



ख) कार्यालय परिसर, छठी मंजिल, "नागिन महल', 82, प्लॉट संख्या 4, ब्लॉक संख्या 1, बैकबे रिक्लेमेशन एस्टेट, सरकार, बॉम्बे, वीर नरीमन रोड, चर्चगेट, मुंबई





4. मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम पर चार (4) अचल संपत्तियां:

क) कार्यालय परिसर संख्या 13 और 14, द्वितीय तल, कृष्णा चेम्बर्स बिल्डिंग, सर्वेक्षण संख्या 541 एबी, 700 से 703 और शहर सर्वेक्षण संख्या 8/4, ग्राम गुलटेडकी पुणे शहर, पुणे नगर निगम, सतारा रोड, कडोलकर कॉलोनी, मुकुंद, पुणे, महाराष्ट्र।











ख) आवासीय फ्लैट संख्या 701, 7वीं मंजिल, विंग सी, "ग्रीन लॉन्स" नामक भवन में, क्रम संख्या 81/6 (पं.), क्रम संख्या 81/8, गांव बेलावली, कल्याण - बदलापुर रोड, बेलावली, बदलापुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र - 421503।













ग) फ्लैट नंबर 301, तीसरी मंजिल और 401, चौथी मंजिल, "न्यू पराग अपार्टमेंट", क्रं.सं 40, एच. नंबर 2 (पी), गांव कत्रप, तालुका अंबरनाथ, जिला ठाणे, महाराष्ट्र।











5. <u>मेसर्स रिलायंस सालगांवकर पावर कंपनी लिमिटेड के नाम पर दो अचल संपत्तियां</u> (मेसर्स रिलायंस सालगांवकर पावर कंपनी लिमिटेड का मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड में



विलय हो गया। इसके बाद, मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड का नाम बदलकर मेसर्स रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और फिर मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया):

क) तालुका मोरमुगाओ, दक्षिण गोवा के सांकोले गांव में भूखंड, जिसे "बोर्डा डे वरजिया गडगल्ली या बोर्डा डे गोडगल" के नाम से जाना जाता है। भूमि सर्वेक्षण संख्या 143/1बी, 150/1ए और 153/1ए (भाग) है।



ख) तालुका मोर्मुगाओ, दक्षिण गोवा के ग्राम सांकोले की भूमि सर्वेक्षण संख्या 153/1ए, जिसे "बोरदा डी वर्ज़िया गडगली या बोर्डा डी गोडगल" के नाम से जाना जाता है।



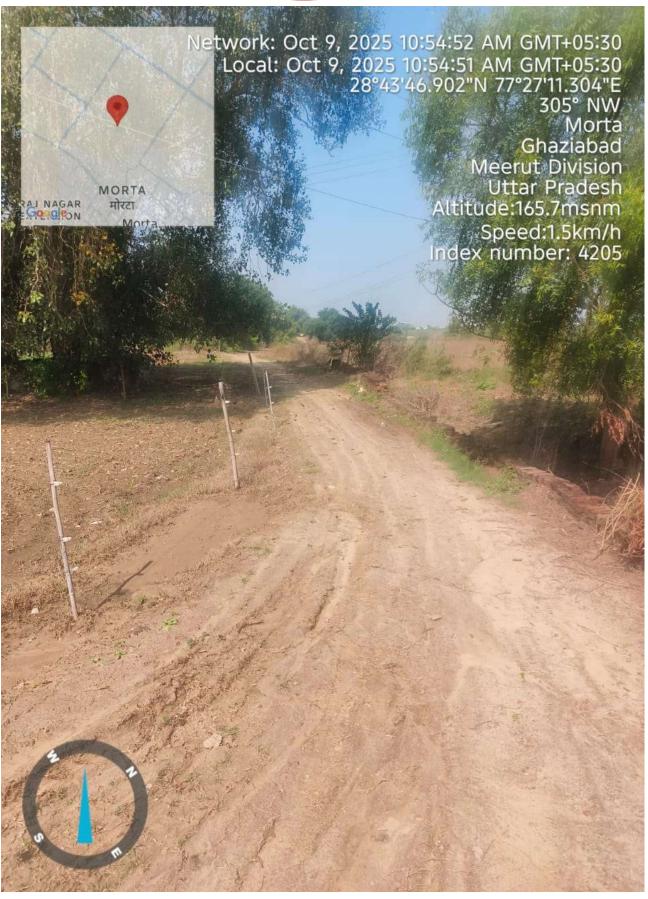


संबद्ध संस्थाओं की संपत्तियां: गाजियाबाद/नोएडा में भूखंड और चेन्नई (अड्यार/ओएमआर-कोट्टिवाक्कम) में 29 फ्लैट:

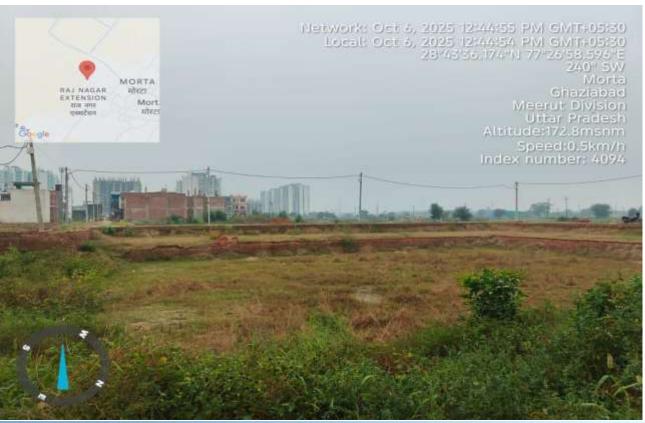
1. मेसर्स आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (5 अचल संपत्तियां) और मेसर्स मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (4 अचल संपत्तियां) के नाम पर अचल संपत्तियां: मेसर्स आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ग्राम मोरटा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 0.278 हेक्टेयर, खसरा संख्या 443, 0.3040 हेक्टेयर, खसरा संख्या 444, 0.361 हेक्टेयर, खसरा संख्या 445, 0.0950 हेक्टेयर, खसरा संख्या 446 और 0.276 हेक्टेयर, खसरा संख्या 503 और 0.548 हेक्टेयर, खसरा संख्या 506 और मेसर्स मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ग्राम मोरटा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 0.424 हेक्टेयर, खाता नंबर 00022, खसरा नंबर 574 और 579, 2.2424 हेक्टेयर, खाता नंबर 00347, खसरा नंबर 584 एम, 1.119 हेक्टेयर, खाता नंबर 00953, खसरा नंबर 570 एम और 572 एम और 0.358 हेक्टेयर, खाता संख्या 00029, खसरा संख्या 584 एम के रूप में क्रमशः भूखंड।





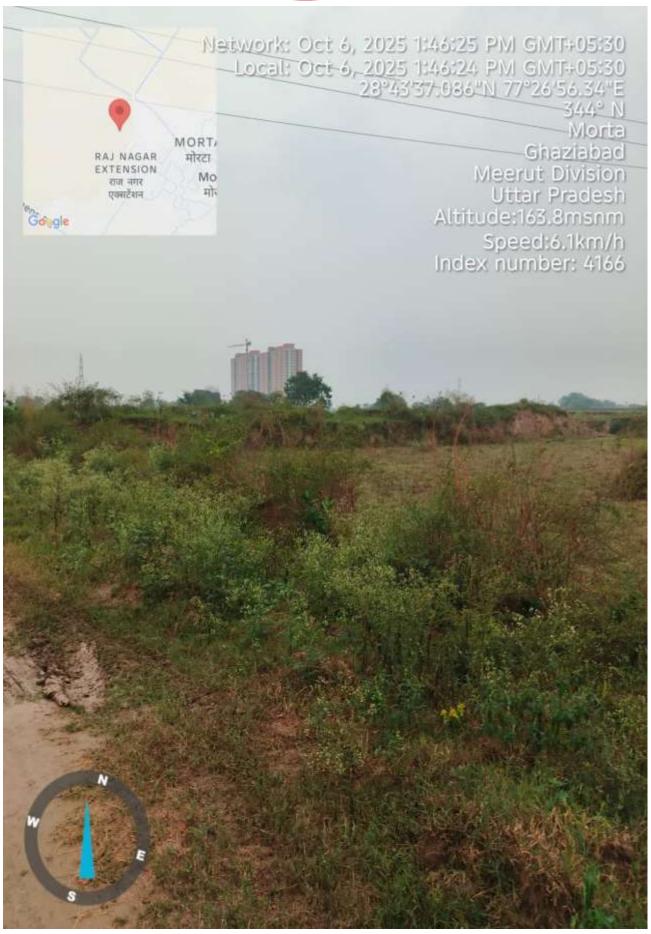




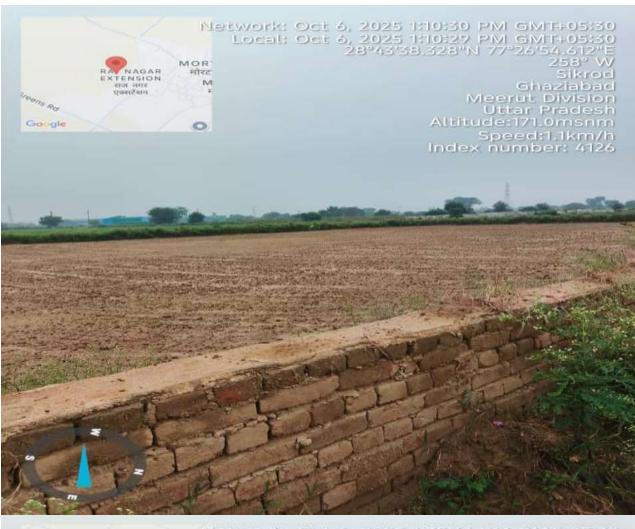






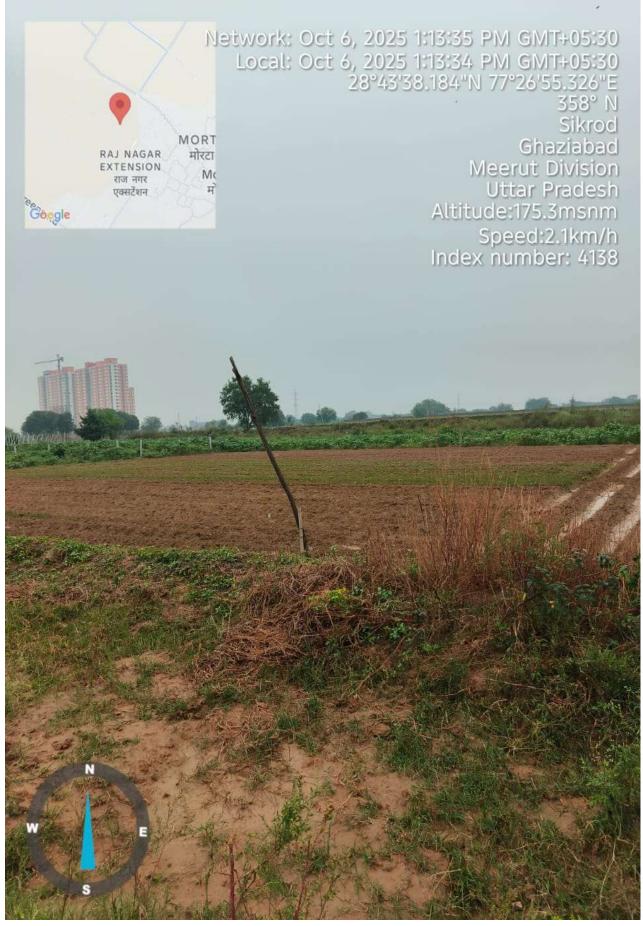




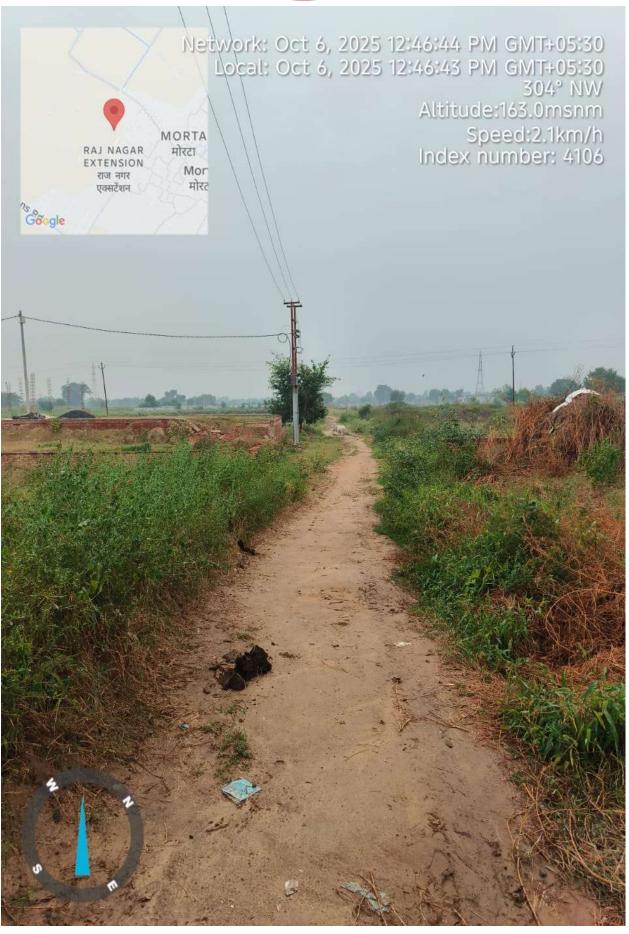






















1. मेसर्स गमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अचल संपत्तियां (29 फ्लैट):

"न्यूटेक एलीवेट 21" नामक परियोजना में सर्वेक्षण संख्या 276/7ए, 276/7बी वाली भूमि पर अवस्थित फ्लैट संख्या 2ए, 2ई, 2एफ, 2जी, 2के, 3ए, 3ई, 3एफ, 3जी, 3के, 4ए, 4ई, 4के, 6जी, 7ए, 7एफ, 9एच, 9जे, 10ए, 10सी, 10जी, 10एच, 10जे, 11ए, 15ए, 15ई, 15एफ, 15एच और 15के (29 फ्लैट), और 276/1 (पट्टा संख्या 4316 सर्वेक्षण संख्या 276/1ए, 276/1बी1, 276/7ए1, 276/7ए2 और 276/7बी के अनुसार), संख्या 141, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, कोट्टिवक्कम गांव, शोलिंगनल्लूर तालुक (पूर्व में तांबरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु) में अवस्थित।

